

सेवा में

माननीय उप-मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय: समिति की जांच में अनियमितता और तथ्यों को छुपाकर गोल-मोल व झूठी आख्या प्रस्तुत करने व अनिल शर्मा, आंकिक द्वारा प्रार्थी के 1,73,350/- रुपये समिति में जमा न कर, गबन करने के बाद भी जांच करने वाले अधिकारी रजनी चतुर्वेदी द्वारा जानबूझकर अनिल शर्मा को बचाने के सम्बंध में।

महोदय

निवेदन है कि मुझ प्रार्थी द्वारा आपके पोर्टल पर दिनांक 01.08.2025 को एक शिकायत जिसका नम्बर 15138250149318 किसान सेवा सहकारी समिति लि० सोसायटी खरखौदा न० 1, ब्लॉक खरखौदा जिला मेरठ में तैनात अनिल शर्मा आंकिक द्वारा प्रार्थी के अंकन रुपये 1,73,350/- का जानबूझकर उसके द्वारा रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि कर रूपयों को गबन किया गया है और जब उससे पूछा गया तो उसने प्रार्थी के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करने व तरह तरह की घमकी देने व वरिष्ठ अधिकारियों व नेताओं से अपने संबंध बताने जिससे कि प्रार्थी, अनिल शर्मा आंकिक द्वारा की गई अनियमितता व फर्जीवाड़ा जो कि रिकॉर्ड में उसने जानबूझकर किया, कि शिकायत किसी उच्च अधिकारी से ना कर सकें। अनिल शर्मा आंकिक के द्वारा की गई प्रार्थी के साथ बदतमिजि और धमकियों से प्रार्थी बुरी तरह डरा गया। फिर प्रार्थी ने हुए भारी नुकसान के कारण शिकायत आपको की जिस पर आपके द्वारा जांच गठित की गई और सारे प्रकरण की जांच प्रार्थी की गैर मौजूदगी में व अनिल शर्मा को पूर्णरूप से उसके द्वारा किये गये अपराध से उसको बचाने के लिए जांचकर्ता अधिकारी रजनी चतुर्वेदी व अन्य अधिकारियों ने काफी प्रयास किया और अन्त में जांचकर्ता अधिकारी रजनी चतुर्वेदी ने अन्य अधिकारियों व नेताओं के दबाव में आकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिससे कि अनिल शर्मा को उसके द्वारा किये गये उक्त अपराध से पूर्णरूप से बचाव हो सकें। जांचकर्ता अधिकारी रजनी चतुर्वेदी ने अपने पद का पूर्णरूप से दुरुपयोग किया है और प्रार्थी किसान को नुकसान पहुंचाने का, अनिल शर्मा आंकिक के द्वारा गैर कानूनी कार्य किया है। प्रार्थी की जानकारी में आया है दिनांक 29.08.

2025 को इसी समिति जिसके द्वारा को प्रार्थी सताया जा रहा है और समिति में खाद गोदाम का ईंचार्ज अनिल शर्मा हैं, इस समिति पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा छापा डाला गया तो सारी अनियमितताये पायी गयी। जांच में 300 बोरे यूरिया, 65 बोरे की बिक्री के रिकॉर्ड को मिलान अनिल शर्मा द्वारा नहीं किया गया। अपर जिला कृषि अधिकारी ने खाद की बिक्री के रिकॉर्ड और रजिस्टर तथा मशीन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस प्रकार अनिल शर्मा द्वारा की गई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच में चांज अधिकारी रजनी चतुर्वेदी के द्वारा अनिल शर्मा को जान बूझकर किसी दबाव में बचाया गया है। प्रार्थी अंकन 1,73,350/- रुपये समिति में जमा कर चुका है, जो अनिल शर्मा को दिये गये हैं। अनिल शर्मा ने जानबूझकर पैसे का गबन किया गया है। यह भी बताना आवश्यक है जो चैकबुक प्रार्थी किसान को मिली ही नहीं, किसी अन्य चैकबुक के चैको का भी इंड्राज रिकॉर्ड मे है जिससे अनियमितता स्पष्ट होती है।

इस प्रकार प्रार्थी जो बहुत ज्यादा पीडित है जिसको आपसे न्याय की बहुत उम्मीद है, आपसे प्रार्थना करता है कि आप प्रार्थी के मामले को गंभीरता से लेकर प्रार्थी के साथ न्याय करायें तथा सारे प्रकरण की जांच पुनः किसी उच्च अधिकारी के द्वारा करायी जायें और प्रार्थी द्वारा जमा धनराशि जो अनिल शर्मा आंकिक द्वारा गबन की गयी है या तो प्रार्थी को मय ब्याज वापस दिलायी जाये या समिति में प्रार्थी के द्वारा जमा की गयी दिनांक से गणना कर शेष धनराशि प्रार्थी से जमा कराकर, प्रार्थी के खाते को बंद कराया जाये। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक:

प्रार्थी

संलग्नक:

विरेन्द्र त्यागी

1. प्रार्थी द्वारा पूर्व मे दिया प्रार्थनापत्र की कॉपी।
2. समिति के कंटिंग रजिस्टर की कॉपी।
3. अखबार में प्रकाशित सूचनाओं की छायाप्रतियां।
4. अनिल शर्मा के निलंबन आदेश की छायाप्रति।

लेन-देन

चैक नं०/ रसीद नं०	कुल धन जो सदस्य से प्राप्त हुआ	धन जो समिति को प्राप्त हुआ				
		असत	सूद	अमानत	हिरसा	दीगार
6/11/14	11/11/14	12531	1133		2210	16
9/8/14	429759					
8-6-14	165520	160000	1157		4300	63
9/1/14						
11/2/14						
27/6/14	36441	112740	10100	1500		
28/6/14	992561					
23/7/14						
28/8/14						
10/9/14	18251	182720	5702			6
5/10/14	57048	5236		1200		6
20/10/14						

का विवरण .

घन जो सदस्य को दिया गया		सदस्य पर लगा ऋण ₹0 ₹10	सदस्य का समिति में जमा		टि. 10 15 20 25
नकद	वस्तु खाद		अमानत वापिस	अमानत	
		02	125531	6000	1
				8200	1
160000			160000	8200	1
				12500	1
187000			187000	12500	1
				12500	1
187000			187000	12500	1
				12500	1
44500				12500	1
21710			21710	12500	1
274000			274000	12500	1
				12500	1

लेन-देन

क्रमांक	वैक नं०/ रसीद नं०	कुल धन जो सदस्य से प्राप्त हुआ	धन जो समिति को प्राप्त हुआ				दीगार
			असल	सूद	अमानत	हिस्सा	
17-6-16		28669	27600	12670			12
18-6-16	992503						
19-6-16	22522	22522	22522	10000			1
30-6-17	952564						
20-6-17	21	222100	222100	10000			11
25-6-18	12588						
30-6-18	12335	12335	12335	8335			18

का विवरण

[illegible]

भ्रष्टाचार के सम्बंध में चैको के फर्जीवाडे के सामान्य बिन्दु

चैक सं.	भ्रष्टाचार विवरण	रकम	दिनांक
429751		40,000 (चालीस लाख)	20.10.2011
429752		51,000 (इक्कयावन हजार)	07.04.2012
429753		6000 (छः हजार)	30.06.2012
429754		50,000 (पचास हजार)	07.10.2012
429755		46,000 (छियालीस हजार)	15.04.2013
429756	चैक किसान के पास ही है।	रद्द कर रखा है	12.06.2013
429757		57,000 (सत्तावन हजार)	12.06.2013
429758		62,000 (बासठ हजार)	11.12.2013
429759		1,60,000 (एक लाख साठ हजार)	07.03.2014
फर्जी चैक	किसान से कोई चैक नही लिया	1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार)	06.03.2014
429760		1,87,000 (एक लाख सत्तासी हजार)	09.04.2014
992561		1,87,000 (एक लाख सत्तासी हजार)	29.06.2014
फर्जी चैक	किसान से कोई चैक नही लिया	2,49,768 (दो लाख उन्नचास हजार सात सौ अडसठ)	तारीख गलत
992562		2,74,000 (दो लाख चौहत्तर हजार)	27.06.2015
992563		2,74,000 (दो लाख चौहत्तर हजार)	18.06.2016
992564		2,74,000 (दो लाख चौहत्तर हजार)	30.06.2017
992565		2,74,000 (दो लाख चौहत्तर हजार)	25.06.2018
992566	राशि जो किसान ने जमा की, समिति रजिस्टर में काटछांट कर बकाया दिखा दिया।	1,73,350 (एक लाख तीहत्तर हजार तीन सौ पचास) मूलधन 1,65,000, मय ब्याज के 1,73,350/6	30.06.2019

उक्त विवरणिका में जो मेरे द्वारा 1,73,350 मय ब्याज अर्थात मूल धन 1,65,350 रुपये जो मेरे द्वारा दिनांक 30.06.2019 में जमा किया गया था वह भी मेरी पासबुक/लेजर/सरकारी रिकॉर्ड में समिति द्वारा काटछांट कर मिटा/हटा दिया है।

1. 1,25,000/- फर्जी चैक से दर्शाया गया धन
2. 2,49,000/- फर्जी चैक से दर्शाया गया धन
3. 1,73,350/- किसान का मय सूद जमा किया गया धन जो समिति द्वारा रजिस्टर में काटछांट कर किसान पर बकाया दिखाया गया धन

कैश स्कॉल सं०

केवल चैक व ड्राफ्ट के लिए
बचत खाता

जिला सहकारी बैंक लि०, मेरठ

लॉग बुक सं०

शाखा

खाता पृष्ठ सं०

दिनांक ३०.६.२०.१९

किस बैंक पर	चैक का क्रमांक	धनराशि	
		रु०	पै०
DCB PHD	992566	165000	
कुल धनराशि रु०		165000	

खाता सं० / Account No.

0255

नाम श्री. सुभाष

धनराशि (शब्दों में) एक लाख पचास हजार

रुपय मात्र

श्री. सुभाष

ह० जमाकर्ता

खजान्ची

लिपिक

ह० आकिफ

व्यवस्थापक

सेवा में

माननीय मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय :- प्रार्थी द्वारा किसान समिति लिमिटेड सोसाइटी, खरखौदा न० 1 ब्लाक खरखौदा जिला, मेरठ से लिये ऋण को समिति द्वारा फर्जीवाडा कर बढ़ाने के सम्बंध में।

महोदय

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त समिति से दिनांक 14.10.2013 को अंतिम बार 62000 रु० ऋण लिया था जिसे समिति द्वारा फर्जीवाडा कर निम्न विवरण के अनुसार अपनी मर्जी से बिना प्रार्थी को बताये बढ़ाया जाता रहा है जो प्रार्थी को आज तक नहीं मिला है।

दिनांक	जमा/निकासी	समिति द्वारा बढ़ाया गया लोन/ऋण
11.06.2013	निकासी	47,000 / - (सैतालिस हजार)
12.06.2013	निकासी	1,25,000 / - (एक लाख पच्चीस हजार)
06.03.2014	निकासी	1,60,000 / - (एक लाख साठ हजार)
09.06.2014	निकासी	1,87,000 / - (एक लाख सत्तासी हजार)
23.06.2014	निकासी	2,49,000 / - (दो लाख उन्नचास हजार)
27.06.2015	निकासी	2,74,7000 / - (दो लाख चौहत्तर हजार)

30.06.2019, जमा	1,65,000 / - (एक लाख पैंसठ हजार)
-----------------	----------------------------------

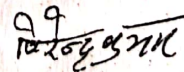
प्रार्थी को पासबुक में एंट्री कराने के बाद पता चला कि उक्त खाते में गलत तरीके सोसायटी द्वारा गलत लेन देन किया जा रहा है जिसका विवरण प्रार्थी द्वारा उक्त तालिका में दिया जा चुका है।

दिनांक 30.06.2019 में प्रार्थी ने समिति को जमा 1,65,000 / - (एक लाख पैंसठ हजार) जमा किया जो प्रार्थी की लोन राशि में नहीं घटाया गया और पासबुक में एंट्री कर दी गयी लेकिन बाद में उक्त एंट्री को समिति के सदस्यों द्वारा रजिस्टर और पासबुक में काट दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। प्रार्थी की जमीन के अनुसार जितना लोन मिलना चाहिए था समिति द्वारा उसकी सीमा से भी कही अधिक लोन प्रार्थी के नाम पर चढा दिया। उक्त लोन के कारण प्रार्थी के खाते को बैंक द्वारा एन.पी.ए. में डाल दिया गया, जिस कारण से अमीन द्वारा दबाव बनाने से प्रार्थी मानसिक रूप से परेशान है। उक्त सभी के समाधान हेतु किसान सेवा समिति के खातो व रजिस्ट्रर की जांच कराकर समिति के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही के आदेश कराया जाए।

अतः आपसे निवेदन है कि समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण की जाँच कराने व दोषियों के विरुद्ध नियम संगत कानूनी कार्यवाही कराने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

दिनांक :-

संलग्नक 1. आचार्य नार्ड
2. पासबुक की फोटो कोपी
3. खाते का स्टेटमेंट
4. जमा की स्लिप

प्रार्थी 

विरेंद्र कुमार त्यागी पुत्र छिदा सिंह त्यागी

निवासी ग्राम कौल, थाना खरखौदा

जनपद मेरठ

मो० नं० - 7037886372. 9897586372

खाद वितरण में धांधली को लेकर सचिव और आंकिक निलंबित

संवाद सूत्र, जागरण • खरखौदा: खाद गोदाम पर बिक्री में धांधली की सूचना के बाद जिला कृषि अधिकारी के आदेश पर 29 अगस्त को हुई छापेमारी में दोषी पाए गए सचिव रविंद्र कुमार यादव व आंकिक अनिल कुमार शर्मा को निलंबित किया गया है। मामले में सहायक विकास अधिकारी रजनी चतुर्वेदी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कस्बे में बी पैक्स नंबर एक पर उर्वरक वितरण कार्य में अनियमितता की सूचना पर जिला कृषि अधिकारी के आदेश पर अपर जिला सहकारी अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी दोनों ने 29 अगस्त को केंद्र पर छापेमारी की थी। जांच में उर्वरक वितरण इं पास मशीन से व आधार काटें देखकर किए जाने संबंधित निर्देशों के होना पाया गया। साथ ही उर्वरक बिक्री की धनराशि 2,81,897 रुपये समय पर जमा न करने का दोषी पाया गया था। जांच में समिति पर कार्यरत सचिव रविंद्र कुमार यादव की समिति कार्यों के प्रति उदासीन कार्य शैली, उर्वरक वितरण से संबंधित

- खाद गोदाम पर बिक्री में धांधली की सूचना पर 29 अगस्त को हुई थी छापेमारी
- अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण करने के लिए सहायक विकास अधिकारी को जिम्मेदारी

महत्वपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण न करने, शिथिल नियंत्रण के कारण विभाग की छवि घूमिल किए जाने जाने का दोषी पाया गया था। जांच के बाद सदस्य सचिव जिला प्रशासनिक कमेटो सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता दीपक कुमार द्वारा सचिव रविंद्र कुमार यादव व समिति आंकिक अनिल कुमार शर्मा दोनों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण करने को सहायक विकास अधिकारी रजनी चतुर्वेदी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। निलंबित अवधि में सचिव बी पैक्स खरखौदा नंबर एक पर ही संबंध रहेंगे। बी पैक्स पश्चिम के सचिव जयशंकर पांडेय को बी पैक्स खरखौदा नंबर एक की भी जिम्मेदारी दी गई है।

खरखोदा में खाद गोदाम

पर छापेमारी, हड़कंप मचा

खरखोदा। अपर जिला कृषि अधिकारी ने मुखवार शाम करवा स्थित सहकारी समिति नंबर एक पर छापेमारी की। छापेमारी में खाद व डीएपी की विक्री में गड़बड़ी मिलने पर विक्री मशीन को कब्जे में लिया।

मुखवार को जिला कृषि अधिकारी द्वारा खाद गोदाम पर मामले की जांच के लिए पहुंचे। मुखवार अपर जिला कृषि अधिकारी ओमपाल पुनिया ने जिला कृषि अधिकारी राजीव सिंह के निर्देश पर सहकारी समिति नंबर एक छापेमारी की। अपर जिला कृषि अधिकारी ने समिति नाचव रविन्द्र यादव व खाद गोदाम राजा अनिल शर्मा से विक्री रजिस्टर

आदि की जांच पड़ताल की। जांच में 300 बोरे खाद और 65 बोरे डीएपी की विक्री के रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो पाने पर अपर जिला कृषि अधिकारी ने खाद और विक्री की मशीन, रिकॉर्ड रजिस्टर आदि अपने कब्जे लिए और जिला कृषि अधिकारी को अवगत कराया। अपर जिला कृषि अधिकारी ओमपाल पुनिया ने बताया कि छापेमारी के दौरान खाद व डीएपी की विक्री में धांधली प्रतीत हो रही है। जिला कृषि अधिकारी राजीव सिंह ने बताया खाद की गाड़ी गोदाम पर पहुंचते ही खत्म होने की सूचना मिल रही थी। संदेह होने पर अपर जिला कृषि अधिकारी को जांच के लिए भेजा है।

यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है इस सरकार में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा खाद की कालाबाजारी यदि की होगी तो कोई भी दो... Read more

Reply



कार्यालय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता मेरठ।

पत्रांक 893 / सह0 / अधिकोषण / 2025-26 /

दिनांक 01/09/25

सचिव/अध्यक्ष/प्रबन्ध, कमेटी,

बी-पैक्स खरखौदा नं0-1,

विकास खण्ड- खरखौदा।

अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील सदर मेरठ व सहायक विकास अधिकारी (सह0) विकास खण्ड खरखौदा ने दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर बी-पैक्स खरखौदा नं0-1 पर पर पाये गये कम उत्तरक रु0 281897.00 की अनियमितता/अस्थायी गबन क दायी होने, कार्यों के प्रति उदासीनता, रोकड़ बही का प्रबन्ध न करने, उत्तरक वितरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण न करने, विभाग की छवि धूमिल करने आदि आरोपों में समिति अधिक श्री अनिल शर्मा को निलम्बित कर वैधानिक/अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री अनिल शर्मा, अधिक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये वैधानिक/अनुशासनिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता मेरठ।

पत्रांक व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0 मेरठ।
2. सहायक विकास अधिकारी (सह0) विकास खण्ड खरखौदा को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
3. अपर जिला सहकारी अधिकारी तहसील सदर मेरठ।
4. सचिव/मुख्यकार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0 मेरठ।
5. संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक महोदय, सहकारिता मेरठ मण्डल मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता मेरठ।

खबर का असर : खरखौदा, खेत का हक डकारने पर सचिव और क्लर्क निलंबित

खरखौदा की बी-पैक्स समिति में बड़ा खेल उजागर, कुर्सी गई

मेरठ के खरखौदा विकास खंड की बी-पैक्स समिति नं-1 में जो खेल हुआ, उसने किसानों के पेट की रोटी पर ही हाथ डाल दिया। खाद का धंधा ऐसे चला जैसे खेत नहीं, कोई दुकानदारी हो। लाखों रुपए का हिसाब गड़बड़ा गया और किसानों की मेहनत की खाद ही सवालियों में घिर गई।

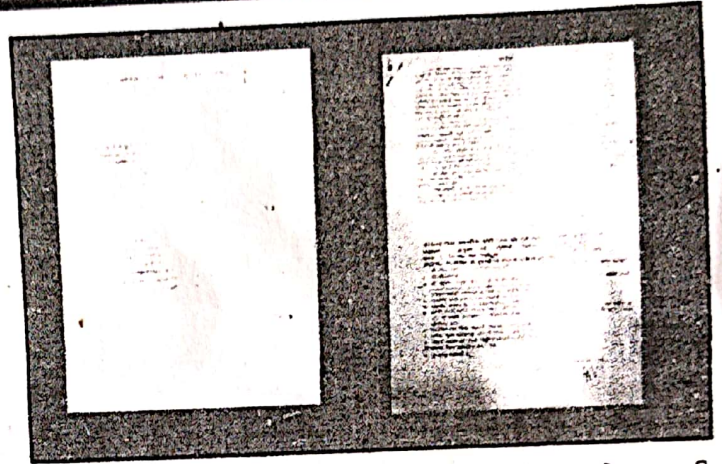
News Highway ने जब ये गड़बड़ी उठाई, तो विभाग की कुर्सियाँ हिल गई। सहकारिता विभाग ने मान लिया कि खेल तो गड़बड़ है। आदेश निकला और देखते ही देखते सचिव रविन्द्र कुमार यादव और आंकिक (क्लर्क) अनिल शर्मा दोनों को निलंबित कर दिया गया।

जांच में निकला कि उर्वरक बेचते समय नियम ताक पर रख दिए गए। पाँस मशीन और आधार कार्ड से बिक्री की जगह सीधे मनमानी चली। 2,81,897 रुपये की रकम का कोई पक्का हिसाब नहीं। रोकड़ बही अधूरी, अभिलेख गायब और किसानों के हक की रकम जैसे जेब में दबा ली गई हो।

सिर्फ इतना ही नहीं, कार्यशैली ऐसी रही कि विभाग की छवि तक बदनाम हो गई। यही वजह रही कि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मेरठ ने आदेश जारी करते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया। अब इनके खिलाफ विभागीय जांच चलेगी। सचिव का प्रभार जयशंकर पाण्डेय को दिया गया है, लेकिन बिना किसी अतिरिक्त वेतन या भत्ते के।

निलंबन के दौरान रविन्द्र कुमार यादव और अनिल शर्मा को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन असली कमाई अब विभागीय कार्रवाई से होगी - गुनाह साबित हुआ तो नौकरी ही चली जाएगी।

विभाग ने साफ संदेश दिया है - "खेती-किसानी में गड़बड़ी की तो कुर्सी नहीं बचेगी। खाद किसानों का हक है, इसे हड़पने वालों को अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।" गाँव-देहात में इस खबर ने आग की तरह काम किया है। किसानों का कहना है कि देर से सही लेकिन कार्रवाई सही दिशा में है।



News Highway की रिपोर्टिंग का असर दिखा और पहली बार विभाग ने मान लिया कि लूट का खेल खेला गया था। अब किसानों की निगाहें जांच पर टिकी हैं। सवाल साफ है - क्या सिर्फ निलंबन से गड़बड़ी की भरपाई होगी या फिर इस लूट के असली जिम्मेदारों को भी जेल तक पहुँचना पड़ेगा?

किन आरोपों में फंसे सचिव और क्लर्क?

जांच में सामने आया कि

- * बिक्री की ₹2,81,897 रकम समय पर बैंक में जमा नहीं की गई। पाँस मशीन और आधार कार्ड से वितरण के नियम का उल्लंघन किया गया।
- * रोकड़ बही और वितरण अभिलेख अधूरे रखे गए।
- * कार्यप्रणाली लापरवाह रही और विभाग की छवि धूमिल हुई।

इन सभी आरोपों को गंभीर मानते हुए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मेरठ ने आदेश जारी किया कि दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच बैठाई जाए।